देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 09.10.2025
समय 07:20

मुख्य समाचार :–

- केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को दवाओं को बाजार में जारी करने से पहले उनके प्रत्येक बैच का अनिवार्य परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हरिद्वार–देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण कार्य का व्यय भार वहन करने का अनुरोध किया।
- स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन ऑथोरिटी की बैठक में करीब 24 करोड़ 68 लाख रुपए लागत की आठ नई कार्ययोजनाओं को स्वीकृति दी गई।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आज देहरादून में दो दिवसीय 'सेब महोत्सव' का आयोजन कर रहा है।

केंद्र निर्देश

केन्द्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से दवाइयों के प्रत्येक बैच के निर्माण और बाज़ार में जारी करने से पहले परीक्षण सुनिश्चित करने के उपाय करने को कहा है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उत्तराखण्ड में रेल अवसंरचना के विकास पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने के लिए इनके विस्तार के साथ ही हरिद्वार–देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य, केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण व्ययभार वहन करते हुए पूरा कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने दोनों रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किये जाने पर सहमति दी उन्होंने कहा कि रेल लाइन दोहरीकरण के केंद्र द्वारा व्ययभार के संबंध में परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने टनकपुर–बागेश्वर रेल परियोजना में संरेखण में अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्रों को भी जोड़ने की संभावनाओं पर विचार करने और टनल के साथ ही सड़क का प्रावधान करने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया। इसके अलावा उन्होंने ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को पूरी तरह बंद करते हुए इस भूमि के सभी अधिकार राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने के लिए भी केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया। रेल मंत्री ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दी। केन्द्रीय रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर देहरादून–टनकपुर साप्ताहिक ट्रेन को सप्ताह में तीन बार किये जाने पर भी सहमति दी।

वन्य जीव सप्ताह समापन

देहरादून के लच्छीवाला रेंज में वन्य जीव सप्ताह का समापन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को लेकर बेहतर काम हुआ है और यही वजह है कि यहां लगातार वन्यजीवों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों का जैव विविधता और पर्यटन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए इनके संरक्षण के लिए मनुष्य की अहम भूमिका भी होनी चाहिए।

जनसंवाद

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर को हुई प्रतियोगी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच को लेकर गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने देहरादून में लोक सुनवाई व जनसंवाद किया। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों, परीक्षा केंद्र प्रभारी, कोचिंग सेंटर संचालक और आम नागरिकों ने अपनी बात और सुझाव रखे। आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, यू.सी ध्यानी ने स्पष्ट किया कि जांच कार्य पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्य च साक्ष्यों पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि आयोग विभिन्न जिलों में जाकर जनता से सीधा संवाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में जो भी सुझाव और साक्ष्य मिल रहे है, उनको संकलित किया जा रहा है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ अंतिम रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जा सके।

सारा स्वीकृति

सचिव, जलागम व स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन ऑथोरिटी– सारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्यभर से जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही करीब 24 करोड़ 68 लाख रुपए लागत की आठ नई कार्ययोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें से लगभग 18 करोड़ 61 लाख रुपए की धनराशि सारा द्वारा आवंटित की जाएगी। श्री जावलकर ने सभी जिलों को "वन डिस्ट्रिक्ट, वन रिवर" की अवधारणा पर आधारित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक जिला अपनी एक प्रमुख या संकटग्रस्त नदी की पहचान कर उसके कैचमेंट एरिया में जल स्रोतों के पुनर्जीवन और संचयन कार्यों को प्रभावी रूप से लागू कर सके। उन्होंने जल संरक्षण कार्यों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने और ग्राम पंचायत स्तर पर धारा–नौला संरक्षण समितियों का शीघ्र गठन करने के भी निर्देश दिए, जो स्थानीय स्तर पर निगरानी का कार्य करेंगी। इन समितियों को सारा द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। श्री जावलकर ने सभी कार्यक्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए ईको–फ्रेंडली संरचनाएँ विकसित करने पर जोर दिया।

सेब महोत्सव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक – नाबार्ड आज से अपने देहरादून कार्यालय परिसर में दो दिवसीय 'सेब महोत्सव' का आयोजन करने जा रहा है। इस दौरान में उच्च गुणवत्ता वाले सेब, कीवी और विशिष्ट पर्वतीय उत्पादों का प्रदर्शन होगा। इसका उद्देश्य उत्तराखंड के सेब और कीवी उत्पादकों और कृषक उत्पादक संगठनों को ग्राहकों से सीधे जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना है। नाबार्ड ने पिछले वर्ष भी 'सेब महोत्सव' का आयोजन किया था और इसकी सफलता से प्रेरित होकर इस वर्ष भी इसे आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में नाबार्ड समर्थित हर्षिल घाटी के कृषक उत्पादक संगठन की ओर से उत्पादित 'ए' ग्रेड रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस सेब उपलब्ध होंगे। इसके अलावा कपकोट के किसानों की ओर से प्राकृतिक विधियों से उगाई गई कीवी व अन्य कृषक उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त उत्कृष्ट पर्वतीय उत्पाद जैसे– अखरोट, राजमा, जीआई टैग वाले उत्पाद, जूस, अचार, हस्तशिल्प और जड़ी–बूटियां बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी।

मेरा सपना मेरा लक्ष्य

बागेश्वर में ''मेरा सपना मेरा लक्ष्य'' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बहुली से आई बालिकाओं ने जनपद के विभिन्न शासकीय कार्यालयों का शैक्षिक भ्रमण किया। इस प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने छात्राओं से सीधे बातचीत करते हुए उनके विचार, सपने और आकांक्षाओं को सुना। जिलाधिकारी ने कहा कि हर सपना तभी साकार होता है, जब उसके पीछे दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास हो।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों की महिला अधिकारियों ने भी छात्राओं से संवाद करते हुए अपने–अपने अनुभव साझा किए और उन्हें विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जानकारी दी। वहीं, छात्राओं ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें नए अनुभव मिले।

पुलिस गिरफ्तार

उत्तरकाशी जिले की डुंडा पुलिस ने 597 नग की खेप के साथ प्रतिबंधित काजल काठ की लकड़ी बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपितों को प्रतिबन्धित लकड़ी के साथ वन विभाग के सुपुर्द किया गया।

गौरतलब है कि काजल काठ की लकड़ी उच्च हिमालय के आरक्षित वन क्षेत्र में पाई जाती है। यह औषधीय दृष्टिकोण से सर्वोत्तम मानी जाती है। भारत, चीन, तिब्बत, नेपाल आदि देशों में इस लकड़ी की तस्करी कर उच्च कीमतों पर बेचा जाता है।